एक अनपेक्षित बजट

लेखक - नौशाद फोर्ब्स (फोर्ब्स मार्शल के सह-अध्यक्ष)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

05 फरवरी, 2020

"बजट में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और मंदी को दूर करने के लिए कोई तत्काल उपाय नहीं बताई गयी है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को एक कम उत्पादकता वाला बजट पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था एक वर्ष में अपनी सबसे कम दर पर बढ़ रही है। कई दशकों की तुलना में अब रोजगार अधिक तनावग्रस्त है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार घाटे की वजह से धीमी पड़ गई है।

जब कंपनियाँ मुश्किल में पड़ती हैं, तो वे इधर-उधर भागने लगती हैं और सब कुछ करने की कोशिश करने लगती हैं, जो लगभग हमेशा विनाशकारी साबित होता है। इसके बजाय, एक तनावग्रस्त कंपनी को ये सब करने से बचना चाहिए और अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिये तथा अपने लक्ष्य को अपने संसाधनों पर केन्द्रित करना चाहिए।

इस वर्ष के केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने वाले उपायों की कमी के कारण मंदी से बाहर निकलना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। बजट के भाग ए में तीन थीम थे, जिनमें से प्रत्येक में तीन विषय थे और इसमें से प्रत्येक में 16 प्वॉइंट्स शामिल थे। इसमें पहला बिंदु उपयोगी था: पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि मॉडल को लागू करने के लिए राज्यों को प्रेरित करना। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर जीवन बीमा निगम की सूची महत्त्वपूर्ण रही।

बजट का भाग बी कर परिवर्तनों पर अधिक केंद्रित और उपयोगी था। इसमें दरों को कम करके और छूट को हटाकर व्यक्तिगत आयकर को सरल बनाना, खंड के लाभांश के तिगुने कराधान को कम करना और कर्मचारी शेयर खरीद के लिए कर रियायतें बढ़ाना शामिल है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बजट में कुछ सकारात्मकता था, लेकिन यह वह बजट नहीं था जिसकी हमें जरूरत थी। इसकी आलोचना के चार कारण हैं।

सबसे पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कारण वर्तमान मंदी की गंभीरता पर कम ध्यान केन्द्रित करना है। उद्योगपतियों के साथ निजी बैठकों में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने वर्तमान आर्थिक संकट और इसके निदान हेतु क्या किये जाने की आवश्यकता है, पर काफी जागरूकता दिखाई थी। हालांकि, यह सब बजट भाषण में स्पष्ट नहीं था। शायद सरकार को अपने स्वयं के आर्थिक सर्वेक्षण पर अधिक भरोसा है, जिसके अनुसार मंदी चक्रीय है और यह जल्द ही अपनी राह पर लौट आएगी या ये भी हो सकता है कि वे ये मान रहे हों कि हमारे आर्थिक तनाव की जानकारी सार्वजनिक हो जाये तो इससे जीवंत भारतीय अर्थव्यवस्था की कथा बिगड़ जाएगी।

दूसरा, बजट में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के दो तात्कालिक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था। सरकारी घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अपने बकाये का भुगतान करने में देरी की है। केंद्र सरकार पर निजी और सार्वजनिक उद्यमों, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लाभार्थियों (उदाहरण के लिए MGNREGA लाभार्थियों) और राज्य सरकारों का 3,00,000 करोड़ रुपये (जीडीपी का 1.5 प्रतिशत) का बकाया है।

अतिरिक्त उधार घाटे का विस्तार करता है और इसका पूर्ण भुगतान अर्थव्यवस्था में तरलता लाता है। इसके अलावा, इस उधार को सरकार को कभी न कभी देना होगा; लेकिन यदि सरकार इसका भुगतान इस वित्तीय वर्ष में करती है तो अगले वर्ष का घाटा कुछ कम हो जाएगा।

अर्थव्यवस्था में अन्य तात्कालिक चुनौती गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (NBFC) से संबंधित है और यह रियल एस्टेट क्षेत्र से सीधे जुड़ी हुई है। एनबीएफसी संकट खपत को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन व्यापक अर्थव्यवस्था को गिरने से रोकने के लिए यह बहुत कम है।

तीसरा, इस बजट में कुछ वास्तविक बुरी चीजें भी शामिल हैं। उनमें से प्रमुख संरक्षणवाद में वृद्धि है। कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। नियमों के पालन के लिए एफटीए के दायरे में आयात की समीक्षा की जानी बाकी है। MSMEs द्वारा बनाए गए उत्पादों की सुरक्षा के लिए जो 'अच्छी गुणवत्ता' के हैं, आयात शुल्क में वृद्धि की गई है।

यह तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सवाल यह है कि गुणवत्ता अच्छी है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? ऐसे उत्पादों का चयन कैसे किया जाएगा? मूल नियमों का पालन कौन करेगा? यह सब देख कर ऐसा लगता है कि बजट के निर्माणकर्ताओं ने

अपने खुद के आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा है, जो दर्शाता है कि मुक्त व्यापार से और एफटीए से भारत को लाभ हुआ है।

चौथा, बजट का अंकगणित बजट के राजस्व को विनिवेश से 1 लाख करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये तक दोगुना करने पर टिकी हुई है। इसका आधा हिस्सा 'रणनीतिक बिक्री' से आना है और हम अभी भी निजीकरण शब्द का उपयोग करने में संकोच करते हैं। एलआईसी का सूचीकरण लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा भी जुटा सकती है। लेकिन इस साल 10 महीने के अंत में हमने केवल 18,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के 20 प्रतिशत से कम है। इसके अलावा, इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि राजस्व में इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप क्या किया जाएगा।

विजय केलकर और अजय शाह की एक नई पुस्तक 'इन सर्विस ऑफ रिपब्लिक' कहती है कि हमें अपने जटिल अर्थव्यवस्था के लिए एक संस्थागत बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना चाहिए, लेकिन हम हम राजनेताओं और नौकरशाहों के विवेक पर भरोसा करते हैं। यदि हम उपर्युक्त कथन के आधार पर इस बजट को देखे तो यह अधिकांश मामलों में विफल प्रतीत होता है।

बजट के 160 मिनट के भाषण में 120 मिनट सभी कार्यक्रमों के बारे में था, जैसे सौर पंपों के लिए योजना, एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय का निर्माण, पाँच पर्यटन क्षेत्रों को कहीं और विकसित किया जाना आदि। इसे लागू करने के लिए सरकारी क्षमता की आवश्यकता होती है, एक ऐसी क्षमता जो प्रदर्शनकारी रूप से अनुपस्थित रही है।

केलकर और शाह की पुस्तक के अंतिम पृष्ठ के अनुसार, निजी क्षेत्र के अधिकारियों मनमानी शक्ति से डरते हैं और इनके आगे कुछ बोल नहीं पाते। खुले तौर इसका विरोध तो नहीं हो पाता है, लेकिन कम निवेश इसी व्यवस्था का एक परिणाम है। निश्चित रूप से, इस बार का बजट वर्तमान अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किए जा रहे मुख्य मुद्दों को नजरअंदाज करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बजट 2020-21 के तहत् एक फोरेंसिक विश्विद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
2. 'इन सर्विस ऑफ रिपब्लिक' डी सुब्बारॉव द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
3. अतिरिक्त उधार से घाटे का विस्तार होता है तथा इसका पूर्ण भुगतान अर्थव्यवस्था में तरलता लाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements.

1. A forensic university will be built as per the budget 2020-21.
2. 'In Service of Republic' is a book written by D. Subbarao.
3. Excess borrowing expands debt and its full payment brings liquidity into the economy.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) All of the above

नोट : 4 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'केंद्रीय बजट 2019-20 आँकड़ों और संभावनाओं दोनों की दृष्टि से एक सकारात्मक बजट नही दिखाई पड़ता है।' इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

'Union Budget 2019-20 does not reflect a positive budget both in terms of data and prospects' Critically analyze this statement. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।